

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल

न्याय अनुभाग - 2

देहरादून : दिनांक : 30 अप्रैल, 2008

विषय: उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित कुटुम्ब न्यायालयों के परामर्शदाताओं के मानदेय में वृद्धि।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1915/यूएचसी/एडमिन-बी/कुटुम्ब न्यायालय /2007, दिनांकित 20.6.2007 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित कुटुम्ब न्यायालयों के परामर्शदाताओं का मानदेय रु० 2000/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रु० 6000/- (छः हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह किये जाने का महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

3. उक्त बढ़ा हुआ मानदेय दिनांक 1.1.2007 से अनुमन्य होगा ।

4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन न्यायालय-04-पारिवारिक न्यायालय-00" के अधीन सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-50-एन०पी०/XXVII(5)/2008, दिनांक 28.4.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)

सचिव ।

संख्या: 07-दो(1)/XXXVI(2)/2008-9-89एक(1)/2004-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
- 2- समस्त प्रधान न्यायाधीश/न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उत्तराखण्ड ।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून, ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, ऋषिकेश एवं रुड़की ।
- 4- परामर्शदाता, कुटुम्ब न्यायालय, पौड़ी गढ़वाल ।
- 5- वित्त अनुभाग-5/एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(क०पी०पाटनी)

अनु सचिव